समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

नाशिक मे किसानों का 'हर खेत काला झेडां' आंदोलन, सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप

Publisher

Published on 15 Sep 2025

नाशिक जिले के किसानों ने हाल ही में "**हर खेत काला झेडां**" **आंदोलन** की शुरुआत की है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकार से अपने चुनावी वादों को पूरा करने की मांग करना है। किसानों का आरोप है कि राज्य सरकार ने चुनाव के समय किए गए **ऋण माफी** और अन्य वादों को अब तक पूरा नहीं किया है।

किसानों का कहना है कि एनडीसीसी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। कई किसानों ने बताया कि बैंक लगातार कर्ज वसूली के लिए परेशान कर रहा है। इसके अलावा, किसानों को समय पर पेमेंट नहीं मिल रही है और उनकी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा। यही कारण है कि उन्होंने अपने खेतों में काले झंडे लहराने का निर्णय लिया।

यह आंदोलन न केवल किसानों की आर्थिक समस्याओं को उजागर करता है, बल्कि यह एक प्रतीक भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में सरकार और वित्तीय संस्थानों की नीतियों का प्रभाव कितना गहरा है। काले झंडे के माध्यम से किसानों ने यह संदेश दिया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा।

किसानों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

1. चुनावी वादों के अनुसार **ऋण माफी** सुनिश्चित करना।
2. एनडीसीसी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्ज वसूली पर रोक लगाना।
3. फसलों का **उचित मूल्य और समय पर पेमेटं** सुनिश्चित करना।
4. कृषि क्षेत्र में आने वाले **संकटों से निपटने के लिए स्थायी नीतियां** बनाना।

किसानों ने अपने खेतों में **काले झंडे लहराए** और कई प्रमुख मार्गों पर शांतिपूर्ण धरना दिया। आंदोलन की खासियत यह रही कि किसानों ने किसी भी तरह का हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। उनका उद्देश्य केवल सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करना था।

स्थानीय प्रशासन ने किसानों से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की अपील की। तहसीलदार ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने में लगी हुई है। इसके अलावा, अधिकारियों ने किसानों से संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का आश्वासन दिया।

किसानों का कहना है कि ऋण माफी और उचित मूल्य न मिलने के कारण वे भारी आर्थिक संकट में हैं। कई परिवारों की आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। बच्चों की पढ़ाई, रोज़मर्रा की ज़रूरतें और कर्ज अदायगी जैसी समस्याएँ किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आंदोलन सरकार के लिए चेतावनी हैं। अगर समय रहते किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो भविष्य में बड़े और व्यापक आंदोलन हो सकते हैं। इसके अलावा, यह आंदोलन किसानों की आजीविका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि उत्पादन के महत्व को उजागर करता है।

इस आंदोलन ने स्थानीय राजनीति और समाज में भी हलचल मचा दी है। कई राजनीतिक दलों ने किसानों के समर्थन में बयान जारी किए हैं। इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग इस आंदोलन के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि किसानों की समस्याओं को हल करना केवल कृषि विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

नाशिक जिले का “हर खेत काला झेंडा” आंदोलन किसानों की आवाज़ है, जो सरकार और वित्तीय संस्थाओं तक अपनी समस्याओं को पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। यह आंदोलन यह दिखाता है कि कृषि क्षेत्र में उचित नीतियाँ और समय पर सहायता कितना आवश्यक है।
आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार किसानों की मांगों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देती है और क्या नीतिगत सुधारों के माध्यम से किसानों की स्थिति सुधारी जा सकती है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.